भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 353

दिनांक 22 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

केरल में डेयरी किसानों को वित्तीय सहायता

353. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में डेयरी उद्योग क्षेत्र संकट से गुजर रहा है और उसे तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है;

(ख) केरल में डेयरी उद्योग के विस्तार के लिए ऋण लेने वाले कुल डेयरी किसानों की संख्या कितनी है, जिसे वे चुका नहीं पाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की केरल में डेयरी उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय पैकेज स्वीकृत करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क), (ग) और (घ) बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार केरल सहित पूरे देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) क्रियान्वित कर रही है। डेयरी फार्मिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले पांच वर्षों में इन योजनाओं के तहत, राज्य को 167.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। योजना के कार्यान्वयन से गोपशुओं और भैंसों की औसत उत्पादकता वर्ष 2014-15 के दौरान 8.31 किलोग्राम प्रति पशु प्रति दिन से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 10.31 किलोग्राम प्रति पशु प्रति दिन हो गई है, जो 24.07% की वृद्धि है। उत्पादकता में वृद्धि के संदर्भ में योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों को मिल रहा है।

(ख) केरल राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वर्तमान में राज्य उन डेयरी किसानों की कुल संख्या का डेटा नहीं रखता है जिन्होंने डेयरी फार्म विस्तार के लिए ऋण लिया है या जिन्होंने समय पर भुगतान में चूक की है हालांकि, पिछले तीन वर्षों से, केरल सरकार का डेयरी विकास विभाग बैंक ब्याज सबवेंशन क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत डेयरी फार्मिंग के प्रयोजनों हेतु लिए गए 3.00 लाख रुपये तक के ऋण पर 100% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पशुपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा का भी विस्तार किया है। अब तक केरल में पशुपालन और डेयरी (AHD) में लगे किसानों हेतु 1,28,361 नए केसीसी जारी किए गए हैं।

******